

नविवारक नरिध

प्रलिमिस् के लयि:

[सरवोच्च नयायालय, नविवारक नरिध, अनुच्छेद 22, उच्च नयायालय के नयायाधीश, दंडात्मक हरिसत, 'सार्वजनिक व्यवस्था', कानून और व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया बनाम बहार राज्य मामले, 1965](#)

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्त्व ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सरवोच्च नयायालय](#) ने माना है कि नविवारक नरिध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लयि केवल "रबर-स्टाम्पिंग प्राधिकारी" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहयि ।

- उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहयि जो राज्य द्वारा शक्ति के अनयितरति उपयोग के साथ ही व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो ।

नविवारक नरिध क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- नविवारक नरिध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में बरटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे ।
- [प्रथम विश्व युद्ध](#) शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारति कयिा गया था, और साथ ही [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के दौरान बनाए गए आपातकालीन नयिमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था ।
 - दोनों में नविवारक नरिध के प्रावधान हैं, यानी किसी व्यक्तिको [वचिारण और दोषसदिधि](#) के बना हरिसत में रखना ।

■ परिचय:

- [नविवारक नरिध](#) का अर्थ है किसी व्यक्तिको नयायालय द्वारा वचिारण एवं दोषसदिधिके बना हरिसत में लेना । इसका उद्देश्य किसी व्यक्तिको [पूर्व अपराध के लयि दंडति करना नहीं](#) है बल्कि उसे निकट भवषिय में अपराध करने से रोकना है ।
- किसी व्यक्तिकी [हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं](#) हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत हेतु पर्याप्त कारण के लयि रिपोर्ट जारी नहीं करता है ।
- [नविवारक नरिध के लयि आधार:](#)
 - राज्य की सुरक्षा
 - लोक व्यवस्था
 - वदिशी मामले, आदि ।

■ हरिसत के दो प्रकार:

- [नविवारक नरिध](#) तब होता है जब किसी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर [पुलसि हरिसत](#) में रखा जाता है कयिे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हाना पहुँचा सकते हैं ।
 - पुलसि के पास किसी भी व्यक्तिको पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हरिसत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजसिट्रेट की अनुमतिके बना गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
- [दंडात्मक हरिसत](#) जिसका अर्थ है किसी दाण्डिक अपराध के लयि सजा के रूप में हरिसत में रखना । यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में कयिा गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयिा गया हो ।

■ सुरक्षा:

- [अनुच्छेद 22](#) गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है ।
 - दो प्रकार के हरिसत - पहला भाग सामान्य [कानूनी मामलों](#) से संबंधति है और दूसरा भाग [नविवारक नरिध के मामलों](#) से संबंधति

है।

- यह अनुच्छेद नविवारक नरिध कानूनों के लयि सलाहकार बोरड के नरिमाण को अनविवार्य करता है, जसिमें **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** बनने के लयि योग्य व्यक्त शिामलि होते हैं।
- वभिनिन कानूनों के तहत, समीक्षा बोरडों को **प्रत्येक तीन माह** में हरिसत के आदेशों का आकलन करना चाहयि, ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके कनिविवारक नरिध के लयि पर्याप्त कारण हैं या नहीं। वे साकष्यों की जाँच करते हैं, यद आवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हरिसत में लयि गए व्यक्त की बात सुनते हैं और फरि रपिरट करते हैं कहरिसत उचित थी या नहीं।
- **हरिसत में लयि गए व्यक्त को उपलब्ध सुरक्षा उपाय:**
 - कसी व्यक्त को केवल **3 माह** के लयि **नविवारक हरिसत** में लयिा जा सकता है।
 - **सलाहकार बोरड** की स्वीकृति के बाद ही हरिसत की अवधि को **3 माह** से अधिक के लयि बढ़ाया जा सकता है।
 - बंदी को अपनी हरिसत के **कारणों को जानने का अधिकार** है।
 - हालाँकि, यद लोकहति में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से **इनकार** कर सकता है।
 - बंदी को उसकी हरिसत को **चुनौती** देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।
- **सापेक्ष नविवारक कानून:**
 - **लोकसुरक्षा अधनियम (PSA)**।
 - **स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधनियम (NDPS), 1985**।
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम: NCRB** डेटा से पता चला है क **राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम (NSA)** के तहत हरिसत में लयि गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई है।
 - **NSA** के तहत नविवारक हरिसत की संख्या वर्ष **2020** में **741** पर पहुँच गई। जबकविवर्ष **2021** में यह संख्या घटकर **483** हो गई।
- **नविवारक हरिसत से संबंधित मुद्दे:**
 - **लोकतंत्र पर प्रश्नचहिन:** वशि्व के कसी भी लोकतांत्रिक देश ने नविवारक हरिसत को संवधान का अभनिन अंग नहीं बनाया है जसा क भारत में कयिा गया है।
 - **अतरिकित न्यायिक प्राधिकरण:** सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग अतरिकित न्यायिक अधिकार का प्रयोग करने के लयि करती हैं, जसिसे नविवारक हरिसत को लेकर चतिाएँ बढ़ जाती हैं।
 - **अन्य अधनियमों का दुरुपयोग: गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधनियम, 1967** जैसे कई कानून हैं जनिका दुरुपयोग नविवारक हरिसत के लयि कयिे जाने की संभावना है।
 - **सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर:** ज़लिा मजसि्ट्रेट तथा पुलसि भी अकसर उभरती सांप्रदायिक झड़पों या कनिही दो समुदायों के बीच हुई झड़पों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लयि संबंधित व्यक्तियों को नयितरति करने के लयि उन्हें नविवारक हरिसत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सार्वजनिक अव्यवस्था न हुई हो।

नविवारक नरिध पर सर्वोच्च न्यायालय:

- **अमीना बेगम केस, 2023:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना क नविवारक हरिसत **आपातकालीन स्थतियों के लयि एक असाधारण उपाय** है और इसे नयिमति रूप से इस्तेमाल नहीं कयिा जाना चाहयि।
 - नविवारक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देना नहीं है बलक **राज्य की सुरक्षा के लयि हानिकारक कसी भी चीज़ को रोकना** है।
- **अंकुल चंद्र प्रधान केस, 1997:** इस मामले में इस बात पर बल दयिा गया क नविवारक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देने के बजाय **राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना** है।

सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था क्या है?

- **परचिय:**
 - **सार्वजनिक व्यवस्था** का तात्पर्य समाज के भीतर शांति, स्थरिता और सद्भाव बनाए रखना है, यह सुनश्चिति करना क गतविधियाँ और व्यवहार समुदाय की समग्र कल्याण या सुरक्षा को बाधति न करें।
 - **सार्वजनिक व्यवस्था भी स्वतंत्र भाषण और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतबिंधति करने का एक आधार है।**
- **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति:**
 - **सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटि 9** के तहत, भारत का संवधान संसद को भारत की रक्षा, वदिशी मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों के लयि नविवारक हरिसत के लयि कानून बनाने की **वशिष शक्ति** प्रदान करता है।
 - **सूची III (समवर्ती सूची) की प्रवषिटि 3** के तहत, संसद और राज्य वधिानमंडल दोनों के पास **सार्वजनिक व्यवस्था** के रखरखाव या समुदाय के लयि आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कारणों से ऐसे कानून बनाने की शक्तियाँ हैं।
 - संवधान की **सातवीं अनुसूची** की **राज्य सूची (सूची 2)** के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है।
- **सार्वजनिक व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था के बीच अंतर:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **'सार्वजनिक व्यवस्था'** और **'कानून और व्यवस्था'** के बीच अंतर कयिा।
 - **राम मनोहर लोहिया बनाम बहिर राज्य मामले, 1965** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना क **'कानून और व्यवस्था'** की समस्या केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावति करती है, लेकनि **सार्वजनिक व्यवस्था** के मुद्दे ने समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर या यहाँ तक क देश को

भी प्रभावित किया है।

- 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर उनके दायरे की डगिरी एवं सीमा में नहित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने" की अभिव्यक्तियों के अंतर्गत लाने के लिये गतिविधियाँ ऐसी प्रकृत की होनी चाहिये कि सामान्य कानून उनसे निपट न सकें या समाज को प्रभावित करने वाली वधिवंसक गतिविधियों को रोक न सकें।

आगे की राह

- **संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC):** नविवारक नरिध प्रावधानों की समीक्षा के बाद वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दो सफारिशें दी गईं:
 - अनुच्छेद 22 के तहत हरिसत की अधकितम अवधि छह महीने होनी चाहिये।
 - सलाहकार बोर्ड की संरचना में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होने चाहिये जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हों।
- **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** जुलाई, 2022 में, तेलंगाना में एक चेन-सनैचर के लिये जारी नविवारक नरिध आदेश को रद्द करते हुए, यह देखा गया कि राज्य को दी गई ये शक्तियाँ "असाधारण" थीं और चूँकि वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिये उनका उपयोग कम-से-कम किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन शक्तियों का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नयितरति करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

Drishti Mains Question

प्रश्न. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में नविवारक नरिध तथा इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये।

वधिक अंतरदृष्टि: [नविवारक नरिध की वैधता](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-5>

